2128. [*Transferred to the 17th December, 1991*]

Rejection of Coca-Cola's previous application for setting up unit in NOIDA

2129. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state whether Coca-Cola's application to set up a 100 per cent Export Oriented Unit in the NOIDA Export Processing Zone in 1990 was rejected if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): After due consideration, it was not found feasible to accept the proposal.

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2130. **डा० अबरार अहमद :**
डा० रत्नाकर पाण्डेय :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने वाली कम्पनियों के नाम क्या-क्या है ;

(ख) वे कब से कार्य कर रही है तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(घ) क्या इन कम्पनियों ने अभी तक उन सभी निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन किया है जो देश में उद्योग स्थापित किए जाने के लिए उन्हें लाइसेंस देने के लिए निर्धारित की गई थी ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा पेप्सी उद्योग के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के कुछ और प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) कम्पनियां सामान्यतः निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है परन्तु सरकार के ध्यान में जब यह आता है कि लाइसेंस की मंजूरी के समय की निर्धारित कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो कानून के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। मेसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया है जिसकी सलाह की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए दो प्रस्ताव एक मैसर्स कैलाग कम्पनी, अमरीका से और दूसरा हांगकांग स्थित कम्पनी मैसर्स जे० एम० आर० पी० सी० ओ० से प्राप्त हुए हैं। जहां नए उपक्रम मैसर्स कैलाग इन्डिया लिमि० में 51% की इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन स्कीम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मै० कैलाग कम्पनी अमरीका को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का अनुमोदन दिया गया है वहां मैसर्स जे० एम० आर० पी० सी० ओ० के प्रस्ताव की विदेशी पूंजी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

2131. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अक्तूबर, 1991 के "दि इकानामिक टाइम्स" में फिशिंग यूनिट्स टू मिस एक्सपोर्ट ओपोर्चूनिटी ड्यू टू गवर्नमेंट एपाथी में" नामक शिर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनेकों उद्यमियों द्वारा गहरे समुद्रों से जल से मछली पकड़ने की अपनी परि

योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिए है, यदि हां, तो अगस्त, 1991 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्र की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन आवेदन पत्रों पर अक्तूबर, 1991 के अन्त तक कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार भविष्य में ऐसे मामलों के तुरन्त निपटान के लिए मार्ग निर्देश बनाने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां । सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि जिन कम्पनियों ने 6 से 8 महीने पहले अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे उन्हें अभी मंजूरी दी जानी है ।

(ख) संयुक्त उद्यमों, पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी पर मार्च, 1991 में नई नीति की घोषणा के बाद उक्त नीति के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अगस्त, 1991 तक 4 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) और (घ) दो आवेदन पत्रों के संबंध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है । शेष दो आवेदन पत्रों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है ।

Allocation of edible oil to Gujarat

2132. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI CHHOTUBHAI PATEL:
SHRI JITENDRABHAI LABHSHANKER BHATT:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any demand has been placed by State Government of Gujarat to the Central Government for the allocation of import edible oil;

(b) if so, what is the monthly demand and alloction for the State for the year 1991-92; and

(c) whether Government propose to import Palmolein oil during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The demand and allocation of edible oil for Gujarat for the year 1991-92, month-wise, are as under:—

(Quantity in MTs)

Month	Demand	Allocation
April, 1991	20,000	Nil
May, 1991	20,000	Nil
June, 1991	20,000	Nil
July, 1991	20,000	Nil
August, 1991	20,000	100
September, 1991	20,000	Nil
October, 1991	20,000	1500
November, 1991	8,000	1500

(c) Yes, Sir.